



PwC का वैश्विक जोखिम सर्वेक्षण, 2023

प्रलिस के लिये:

[साइबर जोखिम](#), [साइबर सुरक्षा](#), [जेनरेटिव आर्टफिशियल इंटेलिजेंस](#), [रैनसमवेयर अटैक](#)

मेन्स के लिये:

भारत में साइबर जोखिम से संबंधित चुनौतियाँ, भारत में साइबर-सुरक्षा के लिये प्रावधान

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

वैश्विक सलाहकार फर्म, PwC के वैश्विक जोखिम सर्वेक्षण, 2023 के अनुसार, [साइबर जोखिम](#) भारतीय संगठनों के लिये सबसे बड़ा खतरा है।

सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

■ साइबर जोखिम:

- साइबर जोखिमों को भारतीय संगठनों द्वारा सामना किये जाने वाले **सबसे बड़े खतरे** के रूप में संदर्भित किया गया है। **38%** उत्तरदाता साइबर खतरों के प्रति उच्च अथवा अत्यधिक असुरक्षित महसूस करते हैं।
 - [जलवायु परिवर्तन](#) (37%) तथा [मुद्रासफीति](#) (36%) भारतीय संगठनों के लिये शीर्ष खतरों में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं।
 - [डिजिटल तथा प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम](#) चौथे स्थान पर हैं, 35% भारतीय व्यापारी इन जोखिमों को लेकर चिंतित हैं।

■ जोखिम प्रबंधन:

- भारतीय संगठन [साइबर सुरक्षा](#) में सक्रिय रूप से नविश कर रहे हैं, अधिकांश लोग आगामी 1-3 वर्षों में साइबर सुरक्षा उपकरण (55%) तथा AI-संबंधित प्रौद्योगिकियों (55%) में नविश की योजना बना रहे हैं, जो वैश्विक रुझानों (क्रमशः 51% व 49%) के अनुरूप हैं।
- इन नविशों को सुदृढ़ करने के लिये **71% भारतीय संगठन सक्रिय रूप से जोखिम प्रबंधन तथा अवसर की पहचान के लिये साइबर सुरक्षा एवं IT डेटा का अनुप्रयोग** कर रहे हैं, जो वैश्विक औसत 61% से अधिक है।
- सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि कैसे संगठन जोखिम प्रबंधन के लिये [जेनरेटिव आर्टफिशियल इंटेलिजेंस](#) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं, 48% भारतीय उद्यमों ने बड़े पैमाने पर स्वचालित जोखिम मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के लिये AI तथा मशीन लर्निंग को प्रयोग में लाया गया है। यह वैश्विक प्रतिक्रिया 50% से थोड़ा कम है।
 - यह रणनीतिक दृष्टिकोण साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने और लचीलेपन के लिये विकसित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रतबिद्धता का प्रतीक है।

■ वरिसत प्रौद्योगिकियाँ:

- 42% भारतीय संगठन पुरानी प्रौद्योगिकियों (पुरानी प्रौद्योगिकी प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे) के कारण **बढ़ी हुई सुरक्षा कमज़ोरियों** से जूझ रहे हैं, जो वैश्विक औसत 36% से अधिक है।
- इसके अलावा 46% भारतीय कंपनियों को पुरानी तकनीक, नवोन्वेषी जोखिम समाधानों के लिये सीमित बजट के कारण रखरखाव से संबंधित लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ता है, जो वैश्विक आँकड़े 39% से अधिक है।

■ नविश में लचीलापन:

- **पछिले वर्ष के दौरान 88% भारतीय संगठनों ने लचीलेपन के निर्माण** में सक्रिय रूप से नविश किया है, जो वैश्विक औसत 77% से अधिक है।।
 - इस नविश में एक टीम शामिल होती है, जिसमें व्यापार नरितरता, साइबर, संकट प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन जैसे कार्यों के सदस्य शामिल होते हैं, जो जोखिम की घटनाओं के घटित होने पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हैं।

साइबर जोखिम भारतीय संगठनों के लिये एक प्राथमिक खतरा क्यों है?

- **मैलवेयर, टरोजन और स्पाइवेयर** से जुड़े साइबर जोखिम प्रमुख रूप से भारतीय संगठनों के लिये सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरे हैं, जो विशेष रूप से रैसमवेयर हमलों में पर्याप्त वृद्धि से उजागर हुए हैं।
 - रोकथाम के बावजूद, इन जोखिमों का इस बात पर बड़ा प्रभाव पड़ता है किबाज़ार उन्हें कैसे देखता है, जो स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करता है और विश्वास को खत्म करता है।
- फरिती का भुगतान करने वाली कंपनियों ने बैकअप पर निर्भर रहने वाली कंपनियों की तुलना में डेटा रिकवरी की लागत दोगुनी हो गई है, जो रैसमवेयर मांगों के आगे घुटने टेकने के वित्तीय नुकसान पर बल देती है।
- IT संगठन महत्त्वपूर्ण डेटा की एक विधि शृंखला संग्रहीत करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी, बौद्धिक संपदा, एक्सेस क्रेडेंशियल और वित्तीय डेटा शामिल होते हैं।
 - यह बहु-आयामी डेटा खतरे फैलाने वालों को कई प्रकार की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने और बनाए रखने के लिये उत्तोलन प्रदान करता है।
 - लीक हुआ डेटा, विशेष रूप से बौद्धिक संपदा, सॉफ्टवेयर के अवमूल्यन और प्रतिकृति को जन्म दे सकता है, जिससे राजस्व धाराओं के लिये गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
- डेटा का आंतरिक मूल्य और संगठन के हतिधारकों पर संभावित प्रभाव से सफल फरिती वसूली की संभावना बढ़ जाती है।

भारतीय संगठनों हेतु साइबर जोखिमों को संबोधित करने वाले कानून:

- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:**
 - यह साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित प्राथमिक कानून है। हैकिंग, सेवा से इनकार करने वाले हमले, फिशिंग, मैलवेयर हमले, पहचान धोखाधड़ी और इलेक्ट्रॉनिक चोरी जैसी गतिविधियों को दंडनीय अपराध के रूप में पहचानना।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:**
 - **DPDP अधिनियम, 2023** वैध उद्देश्यों के लिये ऐसे डेटा के वैध प्रसंस्करण पर ज़ोर देते हुए व्यक्तियों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार को स्वीकार करने वाला कानून है।
 - यह डेटा प्रोसेसर पर जवाबदेही और ज़िम्मेदारियाँ थोपता है। DPDP अधिनियम, 2023 कर्मचारियों और ग्राहकों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के बारे में चर्चाओं को संबोधित करता है, जिससे डेटा गोपनीयता के उच्च मानक को बढ़ावा मिलता है।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013:**
 - इसे खतरे की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिये क्षमताओं का निर्माण, सुभेद्यता को कम करने व राष्ट्रीय सुरक्षा को डिजिटल रूप से सुदृढ़ करके साइबरस्पेस में सूचना एवं बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये डिज़ाइन किया गया है।
 - यह एक सुरक्षा कप्यूटिंग वातावरण सुनिश्चित करने, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में विश्वास को बढ़ावा देने और साइबरस्पेस सुरक्षा के लिये हतिधारकों के कार्यों का मार्गदर्शन करने पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020:**
 - Aims to improve cyber awareness and cybersecurity through more stringent audits. Empanelled cyber auditors will look more carefully at the security features of organizations than are legally necessary now. इसका उद्देश्य अधिक कड़े ऑडिट के माध्यम से साइबर जागरूकता और साइबर सुरक्षा में सुधार करना है। पैनल में शामिल साइबर ऑडिटर संगठनों की सुरक्षा सुविधाओं पर कानूनी तौर पर वर्तमान की तुलना में अधिक सावधानी से ध्यान देने।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

Q.1 भारत में, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना नमिनलखिति में से किसके/कनिके लिये वधिति: अधदिशात्मक है?(2017)

1. सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर)
2. डेटा सेंटर
3. कॉर्पोरेट निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

??????:

Q1. साइबर सुरक्षा के वभिन्न तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, जाँच कीजिये कि भारत ने कसि हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक वकिसति की है। (2022)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pwc-s-2023-global-risk-survey>

